



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2014/माघ 21, 1935

No. 46]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2014/MAGHA 21, 1935

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 फरवरी, 2014

सं. टीएएमपी/6/2010-केओपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, कोलकाता पत्तन न्यास के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/6/2010-केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास

.....

आवेदक

कोरम:

(i) श्री टी. एस. बालासुब्रह्मण्यम, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जनवरी 2014 के 10वें दिन पारित)

यह मामला, कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. केओपीटी का मौजूदा दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/6/2010-केओपीटी, दिनांक 29 नवम्बर, 2010, जिसे 15 फरवरी, 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2013 तक निर्धारित करता है। यह प्राधिकरण केओपीटी के दरमान की वैधता दो बार विस्तारित कर चुका है। इस प्राधिकरण ने केओपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता पिछली बार अपने आदेश दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 द्वारा 31 दिसम्बर, 2013 तक विस्तारित की थी।

3. केओपीटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 30 जनवरी, 2013 द्वारा अपना दाखिल किए गए प्रस्ताव पर संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता एसोसिएशन के साथ विचार-विमर्श किया गया है। हमारे पत्र दिनांक 22 मई, 2013 द्वारा केओपीटी से मांगी गई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण पत्तन द्वारा अपने पत्रों दिनांक 14 अगस्त, 2013 और 20 अगस्त, 2013 द्वारा भेजा गया है। केओपीटी के प्रस्ताव और पत्तन द्वारा प्रेषित जवाबों की जांच की जा रही है और इस प्राधिकरण द्वारा विचार कर अंतिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा।

4. इसी बीच, केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 3 जनवरी, 2014 द्वारा बताया है कि चूंकि संयुक्त सुनवाई खत्म हो चुकी है और यथा अपेक्षित स्पष्टीकरण भेजे जा चुके हैं, इसलिए यह प्राधिकरण मौजूदा दरमान को अंतिम आदेश जारी किए जाने तक विस्तारित करे।

5. इसी बीच, पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में सरकार ने प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता 31 मार्च, 2014 तक अथवा अगले आदेश तक विस्तारित की है। एमओएस द्वारा दी गई सलाह अनुसार, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएएमपी/21/2009-डब्ल्यूएस, दिनांक 20 दिसम्बर, 2013, जिसे जी.सं. 340 द्वारा 26 दिसम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता को विस्तारित किया है।

6. मौजूदा दरमान की वैधता 31 दिसम्बर 2013 को समाप्त हो चुकी है। यह स्वीकार करते हुए कि मामले को अंतिम रूप देने में समय लगेगा और यह भी स्वीकार करते हुए कि द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 की वैधता 31 मार्च, 2014 तक विस्तारित की गई है, यह प्राधिकरण आदेश दिनांक 9 मई, 2013 में दर्ज किए गए कारणों से 4 प्रतिशत अधिभार सहित केओपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2014 तक अथवा संशोधित दरमान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

7. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल 2013 के बाद प्रोद्भूत होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष अगले चक्र के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./143/13]

### TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 4th February, 2014

**No. TAMP/6/2010-KOPT.**—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates at Kolkata Port Trust as in the Order appended hereto.

### TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No. TAMP/6/2010 - KOPT

**The Kolkata Port Trust**

...

**Applicant**

### QUORUM

(i) Shri T. S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

### ORDER

(Passed on this 10th day of January, 2014)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Kolkata Port Trust (KOPT).

2. The existing Scale of Rates of KOPT was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/6/2010-KOPT, dated 29 November, 2010 which was notified in the Gazette of India on 15 February, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2013. This Authority has extended the validity of SOR of KOPT twice. This Authority has last extended the validity of the existing SOR of KOPT till 31 December, 2013 *vide* its Order dated 29 October, 2013.

3. The proposal filed by the KOPT *vide* its letter dated 30 January, 2013 was taken on consultation with the concerned users/user association. The additional information/clarification sought from the KOPT *vide* our letter dated 22 May, 2013 has been furnished by the port *vide* its letter dated 14 August, 2013 and 20 August, 2013. The proposal of KOPT and replies furnished by the port are being examined and it will take time for the case to mature for consideration of this Authority.

4. In the meantime, the KOPT *vide* its letter dated 3 January, 2014 has stated that as the joint hearing is over and as the requisite clarifications have been furnished, that Authority may extend the existing SOR till issuance of the final order.

5. In the meantime, the Government in Ministry of Shipping (MOS) has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 till 31 March, 2014 or until further orders. As advised by the MOS, this Authority has extended the validity of Tariff Guidelines, 2005 *vide* its Order No. TAMP/21/2009-WS, dated 20 December, 2013 which is notified in the Gazette of India on 26 December, 2013 *vide* G. No. 340.

6. The validity of the existing SOR expired on 31 December, 2013. Recognizing that it will take time for finalization of the case and also recognising that the validity of the Tariff Guidelines, 2005 is extended till 31 March, 2014, this Authority extends the validity of the existing SOR of the KOPT including 4% surcharge for the reasons recorded in Order dated 9 May, 2013 till 31 March, 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

7. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return accrues to the KOPT post 1 April, 2013, during the review of its performance, such additional surplus will be fully adjusted in the tariff to be fixed for the next cycle.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Ext./143/13]